निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने में मदद देगा प्रशासन

- निवेशकों को उपयुक्त जमीन के साथ कई रियायतें
- उद्योग बंधु की बैठक में शिकायतों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश

जासं, लखनऊ : ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद दो लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की कवायद में प्रशासन जुट गया है। शुक्रवार को उद्योग बंधु की बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कहा, औद्योगिक पार्क में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए केवल एक प्रतिशत ब्याज दरों पर लोन मिलेगा। इस पर कुल विकास पर होने वाले खर्च का 90 प्रतिशत पैसा सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा निवेशकों को उपयुक्त जमीन दिलाने में भी प्रशासन मदद करेगा। डीएम ने कहा लखनऊ में बड़ी संख्या में निवेशकों ने दिलचस्पी दिखाई है। हम सभी को उनको निराश नहीं करना है। जितने भी इंटेंट उद्यमियों द्वारा भरे गए हैं उनकी इकाइयां जल्द से जल्द स्थापित हो जाएं। इसके लिए सभी विभाग मिलकर काम करें।

जिलाधिकारी ने कहा औद्योगिक भूखंड की समस्या के निस्तारण हेतु प्राइवेट औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया जा रहा है। उपायुक्त उद्योग मनोज चौरसिया ने नई एमएसएमई तथा औद्योगिक नीति में उद्यमियों को दिए जा रहे लाभ तथा निजी औद्योगिक पार्क के विकास के लिए मिल रही रियायतों के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि 10 से 50 एकड़ के निजी औद्योगिक पार्क के अवस्थापना विकास पर आने वाले व्यय का 90 प्रतिशत ऋण राज्य सरकार द्वारा केवल एक प्रतिशत ब्याज पर देने की व्यवस्था शुरू की गयी है। डीएम ने निवेश मित्र पोर्टल पर उद्यमियों द्वारा आन लाइन दाखिल स्वीकृतियां, अनापत्तियां व अनुमतियों के लंबित आवेदनों के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने फूड सेफ्टी एंड ड्रग विभाग, आबकारी विभाग, हाउसिंग विभाग, ग्राउंड वाटर, यूपीसीडा, पावर कार्पोरेशन, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी तथा फिल्म बंधु विभागों के प्रकरण लंबितों पर नाराजगी जताई।

दोहरा टैक्स दे रहे उद्यमी : औद्योगिक क्षेत्र देवा रोड के उद्यमियों को दोहरा टैक्स देना पड़ रह है। नगर निगम द्वारा बिना स्थानांतरण गृहकर नोटिस जारी की गई हैं। उद्यमियों का कहना था यूपीसीडा के साथ नगर निगम को भी गृहकर देना पड़ रहा है। डीएम ने तत्काल नगर निगम और यूपीसीडा को इस समस्या का हल निकालने के निर्देश दिए। सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस चौकी को क्रियाशील करने के निर्देश डीएम ने दिए। यूपीसीडा को निर्देशित किया कि पुलिस चौकी के लिए पुलिस विभाग से पत्राचार करें।

फीडर लगाने के निर्देश : औद्योगिक क्षेत्र में फीडर मार्च तक शुरू करने के निर्देश दिए। अधिशासी अभियंता ने बताया कि सर्वे शुरू हो गया है। इसके पूरा होते ही फीडर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा।